हल्द्वानी (नैनीताल) एवं देहरादून से एक साथ प्रकाशित

समाचारों को विस्तार से व तत्काल पढ़ने के लिए क्लिक करें
Web:- www.jokhimnews.com
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में "A" श्रेणी में सूचीबद्ध

जोखिम

भय भूख एवम् भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत् निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

वर्ष : 16 अंक : 114 हल्द्वानी (नैनीताल) शनिवार 07 मार्च 2026 मूल्य रू 2 पृष्ठ : 8

हल्द्वानी पुलिस ने दो शातिर चोरों को दबोचा

हल्द्वानी (संवाददाता)। जहाँ एक ओर सड़क हादसे के बाद लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वहीं समाज में ऐसे 'गिद्ध' भी मौजूद हैं जो लाशों को लूटने से भी बाज नहीं आते। हल्द्वानी पुलिस ने ऐसे ही दो शातिर चोरों को दबोचा है, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक युवक के वाहन से उसका मोबाइल और सोने की अंगूठी पार कर दी थी।मामला 28 फरवरी का है, जब बरेली रोड निवासी गोपाल सिंह बिष्ट के पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था। बेटे को खोने के गम में डूबे परिवार को तब एक और झटका लगा जब उन्हें पता चला कि हादसे के तुरंत बाद अज्ञात चोरों ने मृतक के वाहन से कीमती मोबाइल और सोने की अंगूठी चोरी कर ली है। पिता की

तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया।एसएसपी के निर्देश पर बिछा जालमामले की संवेदनशीलता और शर्मनाक हरकत को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. ने टीम को तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के जाल की मदद से पुलिस टीम ने गौजाजाली निवासी मौ0 उवेश उर्फ मुन्ना और इन्द्रानगर निवासी मौ0 सैफ अली को धर दबोचा।शत-प्रतिशत माल बरामदपुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से मृतक का विवो मोबाइल और सोने की अंगूठी बरामद कर ली है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस (ठछै) की सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। इस घृणित कार्य को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम की चौतरफा सराहना हो रही है।पुलिस टीमः उ0नि0 रविन्द्र सिंह राणा, कानि0 अनिल जौहरी, कानि0 दिनेश नगरकोटी।

उत्तराखंड महिला फुटबाल संघ की वार्षिक आम सभा में संगठन के नए पदाधिकारियों का चयन

लालकुआं (संवाददाता)। देहरादून स्थित होटल अलकनंदा में आयोजित उत्तराखंड महिला फुटबाल संघ की वार्षिक आम सभा में संगठन के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में प्रदेश में महिला फुटबाल को मजबूत बनाने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।आम सभा में गोदावरी थापली को उत्तराखंड महिला फुटबाल संघ का अध्यक्ष चुना गया, जबकि बिंदुखत्ता निवासी लखन मेहता को संघ का

उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके चयन से क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है और उनसे महिला फुटबाल को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।बैठक में हेमंत थापा को भारतीय महिला फुटबाल महासंघ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं वीरेंद्र दान को प्रदेश उपसचिव तथा नैनीताल जिले का सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई।सभा को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में महिला फुटबाल को बढ़ावा देने, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए संगठित और प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने खेल के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

तेंदुआ जूनस्टेट में सड़क पर चलती एक कार झपट गया

भवाली (संवाददाता)। नगर में गत दिवस की सुबह तेंदुआ जूनस्टेट में सड़क पर चलती एक कार झपट गया। गनीमत रही लोगो ने कार के शीशे

बंद किए थे। जिससे तेंदुए के हमले से कोई हादसा टल गया। लोगों के शोर करने पर तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर गुर्राने लगा। और देखते ही देखते जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए के हमले की सूचना सभासद दीपक कुमार ने वन क्षेत्राधिकारी विजय मेलकानी को दी। सभासद ने बताया कि पूर्व में भी वन्य जीव के हमले से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। एक तेंदुआ पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा है। लेकिन इसके बाद भी तेंदुए की मूवमेंट बनी हुई है। गुरूवार को तेंदुए ने कार सवार पर हमला कर दिया। उन्होंने वन विभाग से पिंजरा लगाने और गशत बढ़ाने की मांग की है।

लोबांज आयुर्वेदिक चिकित्सालय को लेकर फैली अफवाहों पर विराम, स्थानांतरण का कोई प्रस्ताव नहीं - उच्चीकृत चिकित्सालय बनाने की प्रक्रिया शुरू

बागेश्वर (संवाददाता)। हाल के दिनों में कुछ समाचार पत्रों में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लोबांज को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने संबंधी प्रकाशित समाचारों ने क्षेत्रीय जनता में असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इन चर्चाओं और अटकलों के बीच जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. निष्ठा शर्मा कोहली ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लोबांज के स्थानांतरण का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है और चिकित्सालय अपने मौजूदा स्थान पर ही पूर्ववत संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय नियमित रूप से क्षेत्रीय नागरिकों को आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा उपलब्ध सभी सुविधाओं के साथ सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को परामर्श, औषधि वितरण तथा आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्थाएं निरंतर उपलब्ध कराई जा

रही हैं, जिससे स्थानीय जनता के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटक भी लाभान्वित हो रहे हैं। डॉ. कोहली ने यह भी अवगत कराया कि आयुर्वेद विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में चिकित्सालय को उच्चीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया गया है, ताकि यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय को राजकीय भवन में स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी गतिमान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लोबांज अपने वर्तमान स्थान पर ही संचालित रहेगा और क्षेत्र की जनता को आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं पूर्व की भांति निर्बाध रूप से मिलती रहेंगी। विभाग का उद्देश्य न केवल सेवाओं को बनाए रखना है, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त और व्यापक बनाकर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सम्पादकीय

सुर्खियां बनाने की रणनीति

ज्यादा चर्चा गलगोटिया के गड़बड़झाले की ही हुई है, लेकिन बाकी अनेक निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। उन्होंने भी वास्तविक अनुसंधान और आविष्कार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चौंकाने वाली सुर्खियां बनाने की रणनीति अपना रखी है।एआई समिट के दौरान गलगोटिया विश्वविद्यालय को लेकर उठे विवाद का अच्छा असर यह है कि इससे भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रंग-ढंग पर लोगों का ध्यान गया है। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा गलगोटिया के गड़बड़झाले की ही हुई है, लेकिन इस ओर भी ध्यान गया है कि बाकी अनेक निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। उन विश्वविद्यालयों ने भी वास्तविक अनुसंधान और आविष्कार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बनावटी उपलब्धियों के जरिए चौंकाने वाली सुर्खियां बनाने की रणनीति अपना रखी है। बाजार में ये रणनीति दो लिहाज से कारगर रहती है। एक तो इससे दाखिले की दौड़ में शामिल छात्रों को लुभाने में कामयाबी मिलती है, दूसरे ये संस्थान सरकारी अनुदान का भी फायदा उठा ले जाते हैं।इसी मकसद से पेटेंट अर्जियों की संख्या को उन्होंने पैमाना बनाया है। इसे बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित किया जाता है कि संस्थान ने कितनी ऐसी अर्जियां दाखिल कीं। जबकि उन अर्जियों का अंजाम क्या हुआ, इसे छिपा लिया जाता है। मसलन, 2020 से 2025 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 7,096 पेटेंट अर्जियां दाखिल कीं। मगर उनमें से सिर्फ 164 पर पेंटेट हासिल हुआ। मतलब 2.3 प्रतिशत अर्जियां ही सफल रहीं। कमोबेस यही हाल बाकी तमाम प्राइवेट यूनिवर्सटीज का भी है। अगर इनकी तुलना पहले से प्रतिष्ठित आईआईटी, एनआईटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे सरकारी संस्थानों से की जाए, तो उनकी अर्जियों की संख्या काफी कम नजर आएगी, जबकि सफलता दर अतुलनीय रूप से ऊंची दिखेगी।2020-25 की अवधि में इन तमाम संस्थानों की सफलता दर 40 प्रतिशत से ऊपर रही। जाहिर है, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उन संस्थानों में अर्जी परीक्षण की ठोस व्यवस्था है। बहरहाल, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने पेटेंट मिलने के बजाय अर्जी को उपलब्धि का पैमाना बनाया है, तो इसके लिए वे अकेले दोषी नहीं हैं।

लोगों को मूर्ख बनाने का मौका

अजीत द्विवेदी

बिहार में कोई काम नहीं है। सचमुच कोई काम नहीं है। शराबबंदी ने जरूर कुछ लोगों को काम पर लगाया है, जैसे स्कूली बच्चे और बच्चियां अपने स्कूल बैग में शराब की बोतलें ढो रहे हैं। जमीन के कारोबार में भी कुछ भी लोग लगे हैं। हालांकि इनमें भी ज्यादातर काम फर्जीवाड़े का है। जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी है उनकी बात छोड़ दें तो अधिकतर परिवार खेती पर आश्रित हैं। घरों में बूढ़े बचे हुए हैं, जो बाहर कमाने वाले अपने बच्चों की ओर से पैसे आने का इंतजार कर रहे होते हैं।लगभग हर परिवार से एक या उससे ज्यादा व्यक्ति बाहर हैं। जो गरीब है, अक्षम है उसके बच्चे कमाने गए हैं और जो सक्षम है उसके बच्चे पढ़ने गए हैं या पढ़ लिख कर बाहर ही सेटल हो गए हैं। भयावह स्थिति है बिहार में। लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पूरी तरह से गाफिल हैं। उनको न अपनी सुध बुध है और न सरकार की। उनके बदले में जो लोग सरकार चला रहे हैं सब सत्तालोलुप और स्वार्थी लोग हैं, जिन्हें बिहार की बेहतरी से कोई मतलब नहीं है।वैसे बिहार की यह दुर्दशा पिछले करीब चार दशक से है लेकिन अब स्थिति और खराब हो गई है। लेकिन इसमें भी नेता बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पिछले साल दिसंबर में जब एनडीए को दो सौ सीटों से ज्यादा का बहुमत मिला और सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में बिहार में सेमीकंडक्टर हब बनाने, आईटी सिटी बनाने, सेटेलाइट शहर विकसित करने जैसे बड़े प्रस्ताव पास किए गए। लोगों को लगा कि अब उनका जीवन बदलने वाला है। लेकिन बजट आया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, जिससे लगे कि बिहार में कुछ बदलने का प्रयास होगा। अगले साल का बिहार का बजट तीन लाख 47 हजार करोड़ रुपए का है, जिसमें से 74 फीसदी हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में और केंद्र से अनुदान के रूप में मिलेगा।

सोचें, बिहार अपने राजस्व से अपने बजट का सिर्फ 26 फीसदी हिस्सा जुटा पाता है। इसमें भी टैक्स और नॉन टैक्स राजस्व कुल 65 हजार करोड़ रुपए का ही है। बिहार पर चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सरकार का सारा पैसा वेतन, भत्ते, पेंशन, कर्ज का ब्याज आदि चुकाने में खर्च होता है। सरकार के पास राजस्व बढ़ाने की कोई दृष्टि नहीं है और न कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति है। नीति आयोग के आंकड़ों की याद दिलाने की जरुरत नहीं है कि विकास के हर मानक पर बिहार सबसे नीचे है।ऐसी वित्तीय स्थिति वाले राज्य में जब नया हवाईअड्डा बनाने की बात सुनाई दे तो कैसा महसूस होगा? बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक बताए जाते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसे मामलों में उनकी जागरूकता कहां चली जाती है? पिछले दिनों बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पटना से सटे सोनपुर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का ऐलान किया। कहा गया कि इसके लिए 42 सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए 1,302 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दावा किया गया कि यह नवी मुंबई के एयरपोर्ट की तरह होगा। सोनपुर में प्रस्तावित हवाईअड्डे का बजट चार हजार करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का है।

सवाल है कि बिहार जैसे राज्य की प्राथमिकता में पटना के बगल में एक और हवाईअड्डा बनाने की बात कैसे आ सकती है? किसी भी समझदार और बिहार के प्रति ईमानदारी व्यक्ति को बिहार के लिए जरूरी एक हजार कामों की सूची बनाने को कहा जाए तो उसमें भी हवाईअड्डे को निर्माण को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहां सरकार की पहली प्राथमिकता हवाईअड्डा बनाने की दिख रही है।यह कितना गैरजरूरी है इसे बिहार के हवाईअड्डों की स्थिति और हवाई यात्रियों की संख्या से समझा जा सकता है। सोनपुर में जहां नया हवाईअड्डा प्रस्तावित किया गया है वह पटना हवाईअड्डे से अधिकतम 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सो, पहला सवाल तो यही है कि पटना हवाईअड्डे से 25 किलोमीटर दूर एक और हवाईअड्डा क्यों बनाना है? क्या पटना हवाई ट्रैफिक का लोड नहीं उठा पा रहा है?क्या सोनपुर कोई बड़ा औद्योगिक शहर है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और जहां से लाखों टन माल की आपूर्ति होती है? सोनपुर क्या कोई गिफ्ट सिटी है? कोई साइबर सिटी है? ऐसा कुछ नहीं है! फिर भी वहां ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का प्रस्ताव है, जिसे 2030 तक बना देना है। हालांकि सबको पता है कि कुछ नहीं होगा। कोई हवाईअड्डा नहीं बनेगा। सिर्फ इतना होगा कि आसपास की जमीनें महंगी हो जाएंगी और कुछ शरीफ लोग जमीनों में फर्जीवाड़ा करने वालों के जाल में फंस जाएंगे।ऐसा मानने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि बिहार में हवाई जहाज पर चढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से हर दिन नौ से 10 हजार लोग औसतन सफर करते हैं। राज्य के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट दरभंगा हवाईअड्डे से हर दिन दो से ढाई हजार लोग सफर करते हैं। सोचें, यह उत्तर बिहार का इकलौता एयरपोर्ट है। तिरहुत और सारण दोनों कमिश्नरी के अलावा कोशी का पूरा इलाके इसके दायरे में आता है।

140 करोड़ लोगों का देश मात्र एक बाजार

कैसे दिल्ली एआई शिखर समिट भारत बिक्री का मेला था? पहली बात दुनिया ने जाना कि 140 करोड़ लोगों का देश मात्र एक बाजार है। उसकी बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े मंहगे विश्वविद्यालय नकल की भी अक्ल लिए हुए नही हैं। डिग्रीधारी, रट्टामार इंजीनियरों, कर्मयोगियों की भीड़ है मगर कुशल एआई शोधकर्ताओं की संख्या तीन सौ से भी कम है। दुनिया की कथित तीसरी बड़ी आर्थिकी इतनी पोली और कड़की है जो वह अनुसंधान-विकास पर जीडीपी का सिर्फ 0.7 फीसदी खर्च करती है। पूरी भीड, पूरा बाजार और कंपनियां सभी विदेशी उत्पाद, मॉडल तथा ऐप के बूते जिंदा है। दुनिया में बाकी जगह कंपनियां कम से कम एआई उपयोग की कोशिश करती हैं वही भारत की 92 प्रतिशत कंपनियां विदेशी एआई मघॅडल अपना चुकी हैं। टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबला हुआ तो उसके 45 करोड़ दर्शकों के बीच बेचने का सर्वाधिक विज्ञापन स्लॉट चौटजीपीटी का था। मतलब चौटजीपीटी भारत से सर्वाधिक कमाई का रोडमैप बनाए हुए है।तभी दुनिया की हर बड़ी कंपनी का टेक दिग्गज दिल्ली के मेले में दौड़ा आया। सब एकत्र हुए। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक कंपनियों के इन प्रमुखों के हाथ अपने साथ ऊपर उठवा कर मैसेज दिया देखो मेरे साथ भारत के खरीदारों का यह जमावड़ा। वैश्विक खरबपतियों ने मेरे से कितनी उम्मीदे पाली हुई है?

मुझे मेरा ही देखा वह समय याद हो आया जब पिछली आईटी क्रांति में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने प्रोडक्ट की सरकारी बिक्री बढ़वाने के लिए डेमो, कार्यशालाएं आयोजत करती थी। तब भारत में बेचने का वह मार्केटिंग तंत्र था, जिससे प्रोडक्ट प्रस्तुति, डिप्लोमा कोर्स, सरकारी अनुबंध-बिक्री का लंबा-चौड़ा मार्केटिंग अभियान चला था। वैसा ही अब वैश्विक अमेरिकी कंपनियां अपना जाल, अपना नेटवर्क, अपनी चेन में 140 करोड़ की भीड को बंधक बनाने का ब्लूप्रिंट लिए हुए हैं। मैं सन् 1996 से लिखता आ रहा हूं कि भारत आईटी कुली पैदा करने के अलावा अपना कुछ भी नहीं बना रहा। सोचें, भारत सरकार, प्रदेश सरकारों, जनता सब कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट, गूगल ईमेल, सर्च इंजिन, व्हाट्सऐप पर स्थायी आश्रित हो चुके है। आगे अमेरिकी एआई पर होंगे।नया फेज एआई क्रांति है। दिमाग भन्ना गया यह सुन कर कि गूगल के सुंदर पिचई ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को पट्टी पढ़ाई और विश्वगुरू मोदी ने उन्हें एक श्कर्मयोगी॥ का जुमला दिया तो गूगल ने मौका लपका। भारत उद्धार की झांकी बनाते हुए दो करोड़ सरकारी कर्माचारियों को एआई के कृत्रिम दिमाग को अपनाने की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। सोचें, पहली बात, भारत का सरकारी कर्मचारी यदि श्कर्मयोगी॥ होता तो भारत का नागरिक लूटता और भारत मात्र बाजार बना होता?दूसरी बात, ये कर्मचारी पहले से ही सोशल मीडिया (वह भी तो प्रतिदिन सात घंटे ऑनलाइन का प्रतिनिधि है) से टाइमपास करते है तो दफ्तरों में मान्य चौटजीपीटी या गूगल चौट की सरकारी वैधता के बाद कर्मचारी क्या करेंगे? पूरी सरकार (मोदी के पीएमओ से लेकर पटवारी तक) इस फॉर्मूले में एआई का उपयोग करेंगे- एआई बताओं, लिखों राजस्व बढ़ाने का एक नोट, या लोगों को झूठ, भय, भूख, भक्ति में बांधने के उपाय! या लिखे डराने, धमकाने वाला नोटिस, सम्मन, एफआईआर, चार्जशीट का ऐसा मसौदा, जिसे पढ़ कर वकील के भी होश उड़ जाए! और नागरिक रिश्वत ले कर दौड़ा-दौड़ा आए! चेक करो फलां नागरिक के दिमाग का खाता, वह हजारों में रिश्वत देने में समर्थ है या लाखों-करोड़ों में! वसूली में किसकी, कैसी हैसियत है?पता है गूगल ने प्रधानमंत्री से यह भी वायदा किया है कि कंपनी सीधे अमेरिका- भारत के जुडाव के लिए समुद्र में केबल बिछाएगी। भला क्यों? ताकि गूगल या अन्य अमेरिकी कंपनियां डायरेक्ट केबल लिंक से भारत में बेचने का अपना ट्रैफिक, भारत से लूट की कमाई की प्राप्ति का आधुनिकतम पक्का रूप बना लें। सुंदर पिचई ने आंध्रप्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, सरकार के माईबाप जगत सेठ अडानी को भी पटा कर यह बड़ा ऐलान, सौदा पकवा दिया है कि गूगल भारत में विशाल डेटा सेंटर बनाएगी!

संक्षिप्त समाचार...

महर्षि भागीरथ की प्रतिमा स्थल के निकट से शौचालय न हटाने पर आंदोलन की चेतावनी

रुड़की(संवाददाता)। लक्सर विकास समिति ने प्रदर्शन कर बस अड्डे के पास महर्षि भागीरथ की प्रतिमा के निकट से सार्वजनिक शौचालय हटाने की मांग की। इसके बाद तहसील में मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र दास शर्मा को पत्र भी सौंपा। समिति और सैनी समाज के कुछ लोगों ने पूर्व दर्जाधारी रविंद्र सिंह आनंद के साथ महर्षि भागीरथ की प्रतिमा स्थल पर प्रदर्शन किया। कहा कि प्रतिमा के निकट ही शौचालय बनाने से वहां गंदगी और दुर्गंध का बनी रहती है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहा कि तीस दिन के भीतर शौचालय हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

रुड़की(संवाददाता)। पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार देर रात नन्हेड़ा अनंतपुर से सरठेड़ी जाने वाले रास्ते पर पुलिस को एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता मिला। पुलिस को देख वह खेतों की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम वंशराज निवासी नन्हेड़ा अनंतपुर बताया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया।

सरकार की उपेक्षा से आहत राज्य आंदोलनकारी, सीएम को भेजा ज्ञापन

रुड़की(संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुक्रवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा पर गहरी नाराजगी जताई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार का गठन राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, बलिदान और समर्थन से हुआ, वही सरकार आज आंदोलनकारियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आंदोलनकारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है।

नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुड़की(संवाददाता)। नन्हेड़ा अनंतपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग के मामले में घायल युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात नन्हेड़ा अनंतपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर जानलेवा हमला कर फायरिंग कर दी, जिसमें मोहित नामक युवक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के भाई अमन कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही दीपू उर्फ विश्वजीत निवासी नन्हेड़ा अनंतपुर को नामजद कर कार्रवाई की मांग की।

रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा

रुड़की(संवाददाता)। विभिन्न मस्जिदों में रमजान के तीसरे जुमे की नमाज भअकीदत के साथ अदा की गई। नमाजियों की भारी मौजूदगी से मस्जिदों में विशेष रौनक देखने को मिली। लोगों ने नमाज अदा कर गुनाहों की मगफिरत और देश में अमन-चौन व खुशहाली के लिए दुआ मांगी। जामा मस्जिद, मरकज वाली उमर मस्जिद, मदीना मस्जिद, हुसैनिया मस्जिद समेत आसपास के देहात क्षेत्रों की मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अदा की।मुफ्ती शरफराज ने तीसरे जुमे की नमाज अदा कराई और रमजान की बरकतों, रोजा, जकात और फितरे की फजीलत बयान की। मदीना मस्जिद के इमाम मौलवी शरफराज ने अपील की कि इस पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए और जकात व फितरे के माध्यम से गरीबों का सहारा बनें।

लक्सर शुगर मिल ने किया 35.79 करोड़ का भुगतान

रुड़की(संवाददाता)। लक्सर शुगर मिल ने 11 फरवरी से 20 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने का 35 करोड़ 79 लाख रुपये का भुगतान संबंधित गन्ना समितियों को भेज दिया है। अब तक चीनी मिल द्वारा कुल 384 करोड़ 15 लाख रुपये का भुगतान समितियों को किया जा चुका है। उध र समितियां भुगतान को किसानों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। मिल के यूनिट हेड एसपी सिंह ने बताया कि समय पर किसानों के गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 35.79 करोड़ रुपये का भुगतान समितियों को भेज दिया गया है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपना संपूर्ण गन्ना आपूर्ति चीनी मिल को ही करें। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शुगर मिल द्वारा समय पर किसानों का भुगतान किया जा रहा है।

चार साल बाद टूटा गतिरोध, बढ़ा मेजबानी का दायरा

- लेक फेस्टिवल की गतिविधियां इस बार सिर्फ टिहरी में नहीं, कई अन्य जगह भी
- नरेंद्रनगर, घनसाली, प्रतापनगर, धनोल्टी, देवप्रयाग भी इस बार मेजबान
-2021 के बाद नहीं हुआ था आयोजन, कोरोना के कारण लगा था ब्रेक

देहरादून(संवाददाता)। इस बार का टिहरी लेक फेस्टिवल कई मायनों में खास है। सबसे खास बात चार वर्षों से चले आ रहे गतिरोध के टूटने से जुड़ी है। कोविड-19 की वजह से इस आयोजन पर ग्रहण लग गया था। मगर राज्य सरकार ने ठानी, तो इस बार गतिरोध टूट गया। एक और अहम बात काबिलेगौर है। इस बार सिर्फ टिहरी शहर ही इस आयोजन का मेजबान नहीं है, बल्कि मेजबानी का दायरा कई अन्य शहरों तक फैल गया है। यह पहली बार हो रहा है कि नरेंद्रनगर, घनसाली, प्रतापनगर, धनोल्टी और देवप्रयाग जैसे स्थान भी इस आयोजन की मेजबानी कर रहे हैंदरअसल, राज्य सरकार बडेध् आयोजनों को किसी एक जगह पर केंद्रित न रखकर उसे विभिन्न स्थानों पर आयोजित करा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा इस रूप में आता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को बडेध् आयोजन से एक्सपोजर मिलता है। राष्ट्रीय खेलों का उदाहरण हमारे सामने है, जिसे देहरादून के अलावा, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूद्रपुर से लेकर टिहरी, पिथौरागढ़ जैसे स्थानों में भी आयोजित किया गया।टिहरी लेक फेस्टिवल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जबकि देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, धनोल्टी और घनसाली जैसे क्षेत्रों को इस आयोजन से जोड़ा गया हो। इन जगहों पर ट्रैकिंग के इवेंट से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि पहली बार टिहरी लेक फेस्टिवल में टिहरी शहर नहीं, बल्कि पूरा जिला मेजबान बतौर अपनी भूमिका निभा रहा है। टिहरी की डीएम नितिका खंडेलवाल का कहना है कि टिहरी जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो पर्यटन के मानचित्र पर और भी ज्यादा चमक सकते हैं। टिहरी लेक फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों की सहभागिता से अच्छे व सार्थक परिणाम मिलेंगे। टिहरी उत्तराखंड का ऐसा जिला है, जो पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं समेटे हुए हैं। टिहरी झील का आकर्षण तो जगजाहिर है। देश-दुनिया के लोग यहां पर खिंचे चले आ रहे हैं। सरकार यहां पर सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। ताकि टिहरी पर्यटन के मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर पाए। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री।

बैंक में बंधक प्लाट बेचने की डील कर यूपी के शिक्षक से 20 लाख की ठगी

देहरादून(संवाददाता)। बैंक में बंधक प्लाट बेचने की डील कर मुजफ्फरनगर, यूपी के एक शिक्षक से बीस लाख रुपये से अधिक ठग लिए गए। रकम ऐंठने के बाद आरोपी बैनामा करने से मुकर गया। रायपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि अवध विहार कॉलोनी, मुजफ्फरनगर (यूपी) निवासी ओम गोयल ने बताया कि वह पेशे से शिक्षक हैं। वर्ष 2018 में उनका बेटा देहरादून के नेशविला रोड स्थित एक पीजी में रहकर पढ़ाई करता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात पीजी संचालक विभोर कुमार निवासी डंगवाल मार्ग, नेशविला रोड से हुई। दिसंबर 2023 में विभोर ने उन्हें लोअर तुनवाला में अपनी जमीन में से 85.5 गज का प्लॉट 20.53 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया। सौदा तय होने पर ओम गोयल ने टोकन मनी और चेक के माध्यम से भुगतान किया। तीन जनवरी 2024 को दोनों के बीच कचहरी में एग्रीमेंट भी हो गया। ओम गोयल के अनुसार इसके बाद जब वे प्लॉट पर गए, तो वहां आए कुछ लोगों से उन्हें पता चला कि इस जमीन पर पहले से कैनरा बैंक का लोन चल रहा है। जब शिक्षक ने विभोर से सख्ती से पूछताछ की और अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने बेटी के कॉलेज में दाखिले और आर्थिक तंगी का हवाला देकर उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। आरोपी ने एक नया हाथ से लिखित अनुबंध किया और भरोसा दिया कि वह किश्तों में पैसे लेकर प्लॉट का लोन चुका देगा और वहां दो मकान बनाकर मुनाफा साझा करेगा या एक मकान शिक्षक के नाम कर देगा। भरोसे में आकर ओम गोयल ने बैंक से लोन लेकर 19 लाख रुपये का और भुगतान कर दिया।

अधिकारिक वेबसाइट बनाएगा पेंशनर्स संगठन

देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड केंद्रीय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को प्रगति विहार सामुदायिक केंद्र में हुई। इसमें संगठन को प्रभावी बनाने के लिए नई कार्यकारिणी के सदस्यों का नामांकन और विभिन्न समितियों के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधारीकरण के लिए सीजीएचएस की जोनल और लोकल एडवाइजरी कमेटियों के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया गया। साथ ही, संगठन को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट बनाने पर सहमति बनी। बैठक में 10 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली एससीओवीए बैठक के लिए तिलक राज शर्मा और रविन्द्र दत्त सेमवाल को अधिकृत प्रतिनिधि नामित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी, संगठन सचिव श्रीकांत बिमल और लेखा परीक्षक राजेन्द्र उनियाल मौजूद रहे।

उत्तराखंड के तीन आईजी केंद्र में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे

देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पांच मार्च को इनकी तैनाती के आदेश जारी किए गए। आदेश मिलते ही राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए शुक्रवार इनमें दो अधिकारियों को रिलीव कर दिया है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने तीनों अधिकारियों को केंद्रीय सेवा में बुलाए जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार की ओर से गुरुवार को इसका आदेश जारी किया गया। आदेश में मुख्तार मोहसिन (आईपीएस 2005 बैच) को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में डिप्टी डायरेक्टर (डीआईजी स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी बैच की नीरू गर्ग को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में डीआईजी के पद पर तैनाती मिली है। अरुण मोहन जोशी (आईपीएस 2006 बैच) को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में डीआईजी के पद पर तैनाती दी गई है।राज्य में आईजी, केंद्र में संभालेंगे डीआईजी का पदइस डेपुटेशन में एक बड़ी बात यह सामने आई है कि प्रतिनियुक्ति पर जा रहे अरुण मोहन जोशी, मुख्तार मोहसिन और नीरू गर्ग, ये तीनों ही अधिकारी वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। केंद्र में जो उनकी तैनाती तय की गई है, वह उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर हुई है। केंद्र में आईजी पद नामित होने तक इन्हें वहां डीआईजी पद पर काम करना पड़ सकता है।पिछले साल हुए थे डिबार, इस बार सरकार ने खुद भेजे नामइन तीनों आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन का मामला बेहद दिलचस्प है। इस बार अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए स्वयं आवेदन नहीं किया था, बल्कि राज्य सरकार ने ही पहल करते हुए इनके नाम केंद्र को भेजे थे। जानकारी के अनुसार, पिछले साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का आदेश आने के बावजूद वहां ज्वाइन न करने के कारण इन अधिकारियों को केंद्र से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।सरकार की तत्परताअधिकारियों के बिना आवेदन के ही राज्य सरकार ने बीते 16 फरवरी 2026 को इन तीनों के नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिए।

हिन्दी दैनिक जोखिम

सीएम को मिलने जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने खांडखाल में रोका

नई टिहरी(संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने कोटीकॉलोनी जा रहे बांध विस्थापित और प्रभावितों को पुलिस ने खांडखाल में रोक दिया। बांध विस्थापितों और प्रभावितों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। निशुल्क बिजली-पानी देने और बांध से मिलने वाली 12 प्रतिशत रॉयल्टी को टिहरी में विकास कार्यों पर खर्च किए जाने को लेकर सागर भंडारी के नेतृत्व में बौराड़ी के गणेश चौक में गत सात दिनों से बांध विस्थापित और प्रभावितों का धरना चल रहा है। शुक्रवार को कोटीकॉलोनी में चार दिवसीय टिहरी झील महोत्सव शुभारंभ के लिए कोटीकॉलोनी पहुंचे सीएम धामी से मिलने के लिए जा रहे बांध विस्थापित और प्रभावितों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से करीब तीन किमी पहले खांडखाल में रोक दिया। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई जिसके बाद आंदोलनकारियों के सड़क पर शासन-प्रशासन और टीएचडीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया। हालांकि पुलिस के जवान यातायात को सुचारु करने में जुटे रहे।

उन्होंने कहा कि टिहरी बांध की झील में आज जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के महोत्सव और खेल प्रतियोगिताएं हो रही है उनके पीछे टिहरीवासियों का बड़ा योगदान है। टिहरी के विस्थापित और प्रभावित लोगों को निशुल्क बिजली-पानी तक नहीं मिल रहा है। बांध से मिलने वाले रॉयल्टी को टिहरी में खर्च किए जाने के बजाय बाहरी राज्यों में खर्च किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गंगा भगत सिंह नेगी, अजय पंवार, विकास पंवार, देवांक चमोली, बुद्धिपाल परमार, रुकमा परमार, विनीता भंडारी, अशरूफी देवी, प्रतिमा रावत, बबली रावत, कुसुम बिष्ट, रेखा नेगी, मालती राणा, सरोज देवी, शीला पैन्यूली, लक्ष्मी देवी आदि मौजूद थे।

थाना नन्दानगर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, विधि का उल्लंघन करने वाले दो बालकों को लिया संरक्षण में

चमोली(संवाददाता)। नरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम श्रीकोट कुमजुग ने थाना नन्दानगर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों ने दोपहर में उनके घर का दरवाजा तोड़कर आलमारी से गहने और कपड़े चोरी कर लिए हैं। तहरीर के आधार पर थाना नन्दानगर पर तत्काल मु0अ0सं0 03/2026, धारा-305(क), 331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उपनिरीक्षक मनोज भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर सुरागरसी और पतारसी को सक्रिय किया गया। गहन छानबीन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकरण में दो नाबालिगों की संलिप्तता प्रकाश में आई। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार उनके अभिभावकों की उपस्थिति में दोनों नाबालिगों को संरक्षण में लिया गया जिनसे 01 जोड़ी चांदी की पायल, 02 चांदी के कंगन और चोरी के कपड़े बरामद हुए। पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की संगति और उनकी दैनिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें। यदि बच्चा अचानक बिना किसी आय के स्रोत के कीमती सामान या नए कपड़े लाता है, तो उससे पूछताछ अवश्य करें। बच्चों को बचपन से ही सही और गलत के बीच का अंतर समझाएं। उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व बताएं ताकि वे कम उम्र में अपराध की ओर आकर्षित न हों।

मार्ग के लिए आंदोलन जारी, मिल रहा समर्थन

श्रीनगर गढ़वाल(संवाददाता)। कीर्तिनगर विकासखंड के पांडव गांव में ग्रामीणों का पांडव मार्ग को नैलचामी-गंडराखाल मार्ग से जोड़ने की मांग के लिए चल रहा धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन आंदोलन को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने समर्थन दिया। ग्रामीणों ने कहा यदि उनकी मांग पर अमल नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। लोस्तु बडियार समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप गोदियाल ने कहा कि पांडव मार्ग को नैलचामी-गंडराखाल से जोड़ने से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। मार्ग बनने से घनसाली, नैलचामी वाला क्षेत्र बडियारगढ़ से जुड़ जाएगा जिससे लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर रामलाल गोदियाल, धर्म सिंह बर्त्वाल, वीरबल सिंह, कुलदीप सिंह, कमल सिंह, प्रताप सिंह, सुदामा प्रसाद गोदियाल, महावीर प्रसाद, हरीश प्रसाद, मंशाराम और नैन सिंह आदि मौजूद रहे।

गुलदार ने 17 बकरियों को मार डाला, दहशत मचा

रुद्रप्रयाग(संवाददाता)। विकासखंड अगस्त्यमुनि के ग्रामसभा जरम्वाड़ के ढुंग गांव में गुलदार ने दो किसानों दिगपाल सिंह नेगी और सज्जन सिंह नेगी की 17 बकरियों को मार डाला। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं संबंधित किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार की दहशत से निजात दिलाने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन कांडपाल ने कहा कि क्षेत्र में लगातार मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां बंदर, सुअर और लंगूर किसानों की फसलों को बरबाद कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर गुलदार मवेशियों को मार रहे हैं। इससे ग्रामीणों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

टिहरी लेक फेस्टिवल की फुटबाल टूर्नामेंट के खिलाड़ियों ने निकाला मार्च पास्ट

नई टिहरी(संवाददाता)। टिहरी झील महोत्सव के तहत बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित जनरल केएम करियप्पा फुटबाल टूर्नामेंट के खिलाड़ियों ने जिला मुख्यालय के वसंत बिहार से स्टेडियम तक मार्च पास्ट निकाल कर लोगों को खेलों प्रति जागरुक करने का प्रयास किया। टिहरी झील महोत्सव के तहत कराए जा रहे फुटबाल मैच में 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।डीएम नितिका खंडेलवाल और पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने मार्च पास्ट टीम को हरी झंडी दिखाकर स्टेडियम के लिए रवाना किया। डीएम ने कहा कि करियप्पा फुटबाल टूर्नामेंट की शुरूआत 1951 में पुरानी टिहरी से हुई थी। अब यह टूर्नामेंट हर वर्ष नई टिहरी में भी कराया जाएगा। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि टिहरी के पर्यटन को पहचान देने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। महोत्सव के तहत स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय जनरल केएम करियप्पा फुटबाल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उनमें ओल्ड स्टार टिहरी, टिहरी यंग, नॉर्थ कमांड, आईआईएमटी मेरठ, 13 गढ़वाल राइफल, 16 गढ़वाल राइफल, पिथौरागढ़ एफसी, हरियाणा सिटी एफसी, आरआरएफसी रुद्रप्रयाग, नोएडा एफसी, दून वारियर्स एफसी, यंग स्टार देहरादून, कोटद्वार एफसी, दिल्ली पुलिस, गढ़वाल हीरोज दिल्ली और सम्राट स्पोर्ट्स की टीमें शामिल हैं।

मारपीट मामले में पुलिस ने बाइक सीज की

पौड़ी(संवाददाता)। होली के दिन कीर्तिनगर बाजार में व्यापारियों के साथ हुई मारपीट की घटना के अन्य आरोपियों की खोज की जा रही है। कोतवाली निरीक्षक संजय मिश्रा ने कहा कि इस मामले में व्यापारियों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पूछताछ जारी है। मौके से मिली बाइक को सीज कर दिया गया है। बाइक स्वामी कोई और था और बाइक चला कोई और रहा था। इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस पहले ही शांतिभंग के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शराब की दुकान एक सप्ताह में हटाएं

पौड़ी(संवाददाता)। पुलिस चौकी के पास संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान को स्थानीय लोगों ने एक सप्ताह के अंदर हटाने जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि उक्त दुकान नेशनल हाईवे से सटी हुई है। सड़क सुरक्षा को देखते हुए दुकान को यहां से हटाया जाना जरूरी है। कहा कि आए दिन यहां पर लड़ाई-झगड़ा हो जाता है जिससे नगर का माहौल खराब हो रहा है। लोगों ने एसडीएम कीर्तिनगर से मिलकर दुकान को एक सप्ताह में हटाने की मांग की। कहा यदि मांग पर अमल नहीं हुआ तो लोगों प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। एसडीएम से मिलने वालों में एडवोकेट चंद्रभानु तिवाड़ी, आशा पैन्यूली, ओमप्रकाश बधानी, जयप्रकाश जोशी, सविता उनियाल, विकास दुमागा, जगदंबा कुमांई और सरोजनी देवी आदि मौजूद रहे।

हाईवे के सुधारीकरण कार्यों का बीआरओ के अधिकारियों ने किया निरीक्षण

चमोली(संवाददाता)। सिमली-कर्णप्रयाग हाईवे पर चल रहे सुधारीकरण कार्यों का बीआरओ के 123 आरसीसी के कमान अधिकारी मेजर विवेक सोनी ने निरीक्षण कर जायजा लिया। नारायणबगड़ भूस्खलन क्षेत्र में बरसात के दौरान हाईवे को दुरुस्त रखना बीआरओ के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहता है। हाईवे के नीचे पिंडर नदी के कटाव के कारण भूधंसाव होने से यहां हाईवे का 500 मीटर हिस्सा लगातार क्षतिग्रस्त होता रहता है जिसकी रोकथाम के लिए बीआरओ को जालीदार पत्थरों की कच्ची दीवारों का निर्माण हर वर्ष करना पड़ता है। इस अवसर पर ओसी मेजर विवेक सोनी के साथ 66 आरसीसी के सहायक अभियंता जस्सू सिंह और अवर अभियंता राधेश्याम भी मौजूद रहे।

ग्वालदम में बढ़ने लगी पानी की किल्लत

चमोली(संवाददाता)। गर्मी बढ़ते ही ग्वालदम में पेयजल किल्लत होने लगी है। अनियमित पेयजल आपूर्ति से बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी बढ़ रही है। ग्वालदम कस्बे की तीन हजार से अधिक की जनसंख्या की पानी की किल्लत दूर करने के लिए वर्ष 2016-17 में 15 करोड़ की लागत से पिंडर नदी से पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण किया गया लेकिन असमान वितरण प्रणाली के कारण यहां गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की किल्लत बढ़ जाती है। प्रधान हेमलता गाड़िया व्यापार संघ अध्यक्ष अनिल नेगी, हरीश जोशी, सुशीला गड़िया, धीरेंद्र सिंह का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद पेयजल की दिक्कत कम नहीं हो रही है। जल संस्थान को तत्काल इस पर कार्य करना चाहिए। वहीं जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता अंशुल कपरूवाण ने कहा कि पाइप लाइन में कबाड़ फंसने से पानी सही तरीके से पंप नहीं हो रहा था। अब पाइप लाइन की सफाई कर दी गई है। जल्द पानी की आपूर्ति नियमित कर दी जाएगी।

भराड़ीसैंण में बजट सत्र को लेकर पुलिस ने किया पुलिस ने जारी किया रूट चार्ट

चमोली(संवाददाता)। भराड़ीसैंण में नौ से 13 मार्च तक होने वाले विधानसभा बजट सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का रूट चार्ट तैयार किया है। एसपी चमोली सुरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों, वीआइपी व्यक्तियों, अधिकारियों/कार्मिकों तथा आम जनता का आवागमन रहता है। ऐसे में आमजन को आवागमन सुविधा मिले इसके लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण-भराड़ीसैंण नगर क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा।

बदरी-केदार धाम में विशेष पूजा हो सकती है महंगी, बीकेटीसी कर रही शुल्क में बढ़ोत्तरी पर विचार

चमोली(संवाददाता)। इस बार चारधाम यात्रा में बदरी-केदार धाम आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष पूजा के लिए जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति दोनों धामों में विशेष पूजा के शुल्क में बढ़ोत्तरी पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव 10 मार्च को देहरादून में होने वाली समिति की बोर्ड बैठक में रखा जाना है। यदि इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो विशेष पूजाओं का शुल्क 15 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में महाभिषेक, आरती सहित अन्य विशेष पूजाएं मंदिर समिति की वेबसाइट पर बुक की जाती है। आफलाइन पूजा के लिए मंदिर समिति के कार्यालयों के काउंटरों पर भी शुल्क जमा किया जाता है।

पेयजल एवं सीवर पाइपलाइन के कार्यो की समीक्षा बैठक

हल्द्वानी (संवाददाता)। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम सभागार में महापौर गजराज सिंह बिष्ट द्वारा यूयूएसडीए द्वारा स्वीकृत रोड पेयजल एवं सीवर पाइपलाइन के कार्यों की समीक्षा बैठक रखी गई !

जिसमें पार्षदों द्वारा अपने अपने वार्डों में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया व वार्डों में होने वाले विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई !तत्पश्चात यूयूएसडीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए महापौर ने कहा कि आगामी होने वाली बरसात से पहले सभी खुदी सड़कों, पेयजल तथा सीवर का कार्य पूर्ण कर लिया जाए । महापौर गजराज बिष्ट ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जिस किसी सड़क का कार्य किया जाना है उस क्षेत्र में दो-तीन दिन पहले से अनाउंसमेंट कर जानकारी दी जाए व उचित साइन बोर्ड लगाए जाएं !महापौर ने यह भी कहा कि अभी पुरानी खुदी सड़कों के सही होने तक नई सड़को को ना को खोदा जाए !पार्षदों द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर से शिकायत की गई, जिसमें महापौर गजराज सिंह बिष्ट द्वारा नगर आयुक्त परितोष वर्मा से 15 दिन के भीतर सारी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया बैठक में नगर आयुक्त परितोष वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मनोज कांडपाल, ए ई नवल नौटियाल, पार्षद बबली वर्मा, तनुजा जोशी, विद्या देवी, नीमा भट्ट, राजेश पंत, रुक्मणी बिष्ट, धर्मवीर, रईस अहमद, नवीन चंद्र जोशी, चंद्रप्रकाश, संजय पांडे, रेखा बेनीवाल, नेहा अधिकारी, ज्योति पांडे, मुकुल बल्यूटिया,अमित सिंह,यूयूएसडीए से प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप कुमार, ए ई दीनदयाल पांडे, रोहित जोशी, मनोज चंद्र, दिनेश चंद्र आर्य, प्रदीप मेहरा, आदि लोग उपस्थित रहे !

भारी धूल का समाना करना पड़ रहा

हल्द्वानी (संवाददाता)। /राजपुरा खनन गेट से हर दिन सैकड़ों डंपर घनी आबादी से गुजरते हैं पानी के छिड़काव न होने से इलाके वासियों को भारी धूल का समाना करना पड़ रहा है।जिससे गुस्साए लोगों ने युवा नेता पार्षद

प्रतिनिधि हेमन्त साहू के अगवाई में खनन गेट के कर्मचारियों का घेराव कर कड़ी नाराजगी जाहिर करते पानी के छिड़काव न होने पर खनन गेट बंद करने की चेतावनी दी।साहू ने मौके पर डीएलएम से फोन वार्ता कर कड़ा आक्रोश जतायासाहू का कहना है पानी का छिड़काव न होने के कारण स्थानीय जनता धूल की वजह से बीमार हो रही है वन निगम की कार्यप्रणाली शर्मनाक है। डीएलएम ने जल्द व्यवस्था करने की बात कही तब जाकर लोग शांत हुए। इस मौके पर हरिमोहन रंधावा बब्बू दिवाकर विपिन चौहान विजय कुमार सोनू कुमार समेत तमाम लोग थे।

जिलाधिकारी ने नागरिकों हेतु आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर जारी किये

हल्द्वानी (संवाददाता)। जनपद नैनीताल का कोई भी निवासी खाड़ी देश में फंसा हुआ है, तो उनके संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल नंबर पर सूचित कर सकते हैं, ताकि समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि खाडी देशों में चल रहे सैन्य संघर्ष को देखते हुए कुवैत, सऊदी अरब,बहरीन तथा यूएई देशों में फंसे जनपद के नागरिकों हेतु आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर जारी किये गये हैं, ताकि सुरक्षित भारत वापसी के संबंध में शासन-प्रशासन स्तर पर आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कुवैत हेतु मो-96565-501946, ईमेल community-kuwait@mea-gov-पद, सऊदी अरब हेतु मो-00-966-11-4884697 तथा ईमेल cw-riyadh@mea-gov-पद, बहरीन हेतु मो-97339-418071,97338-400433, यूट्यूब म्उइेंल वि पदकपं, ठीतंपद तथा यूएई हेतु मो- 971-2-4492700 तथा बैब साईट wwwwww-indembassyuae-gov.पद पर सूचित कर सकते हैं ताकि समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि केवल आधिकारिक व सत्यापित सूचनाओं पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें।

मुक्तेश्वर में बेलगाम निर्माण पर आयुक्त का डंडा, अवैध इमारतों की जांच के निर्देश

नैनीताल (संवाददाता)। जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने क्षेत्र में तेजी से बन रही बहुमंजिला इमारतों और रिसॉर्ट्स को लेकर गंभीर चिंता जताई है। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कुछ लोगों द्वारा समूह बनाकर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही होमस्टे योजना का लाभ भी लिया जा रहा है।आयुक्त ने प्रथम दृष्टया इन निर्माणों को भू-कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी इमारतों का निर्माण और योजनाओं का दुरुपयोग गंभीर मामला है तथा इससे भू-कानून की भावना प्रभावित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में भू-कानून का व्यापक दुरुपयोग होने की आशंका है।प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने जिलाधिकारी नैनीताल और जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि क्षेत्र में बन रही ऐसी सभी इमारतों और रिसॉर्ट्स की विस्तृत जांच की जाए। साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।उन्होंने कहा कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन या अनियोजित निर्माण की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के निर्माणों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि भू-कानून का दुरुपयोग रोका जा सके।

अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया

हल्द्वानी (संवाददाता)। शहर के उंचापुल क्षेत्र में लंबे समय से लग रहे जाम और अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। प्रशासनिक टीम ने सिंचाई नहर की भूमि पर बनाए गए दो बड़े अवैध भवनों को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई और नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि सिंचाई नहर की भूमि पर अवैध रूप से दो मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई थीं, जिनमें कई दुकानें संचालित हो रही थीं। इन निर्माणों के कारण उंचापुल क्षेत्र में अक्सर यातायात बाधित रहता था और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था।प्रशासन के अनुसार इन अवैध निर्माणों को पहले ही चिन्हित कर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी। अभियान के दौरान भवनों को तोड़ते हुए नहर की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं, वे स्वयं उन्हें हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हुड़दंग और लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ गई

हल्द्वानी (संवाददाता)। /रंगों और उमंग के त्योहार होली के दौरान कई जगहों पर हुड़दंग और लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ गई। शहर के प्रमुख अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायल और बीमार लोग इलाज के लिए पहुंचे। खासतौर पर आंखों में रंग और धूल जाने से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। डॉक्टरों के अनुसार बीते 24 घंटे में शहर के प्रमुख चिकित्सा संस्थान ज्ञपदह ळमवतहम' डमकप. बंस न्दपअमतेपजल (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में कुल 248 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से लगभग 70 लोग आंखों की समस्या से पीड़ित थे।डॉक्टरों के मुताबिक होली खेलने के दौरान कई लोगों की आंखों में रंग, धूल और अन्य कण चले गए, जिससे उन्हें तेज जलन, संक्रमण और देखने में परेशानी की शिकायत हुई। कुछ मरीजों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत इलाज और निगरानी में रखना पड़ा।विशेषज्ञों ने बताया कि कई मामलों में रंगों में मिले रासायनिक तत्वों की वजह से आंखों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। यही कारण है कि डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनने जैसी सलाह पहले ही दी थी।

हिन्दी दैनिक जोखिम

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को हरिद्वार में 'जन-जन की सरकार : चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग

- कार्यक्रम को लेकर शासन-प्रशासन की सभी तैयारियाँ पूर्ण

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए सज-संवर रहा है हरिद्वार शहर

- मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरिद्वार का भ्रमण कर कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

देहरादून(संवाददाता)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार, 7 मार्च 2026 को हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम 'जन-जन की सरकार : चार साल बेमिसाल' में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं तथा अमित शाह के स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल बैरागी कैम्प के साथ ही हरिद्वार शहर को सजाया-संवारा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार का भ्रमण कर इस विराट आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैरागी कैम्प पहुँचकर प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा स्थल, मंच, प्रदर्शनी क्षेत्र, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तृत अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एवं सुचारु आयोजन के लिए सभी तैयारियों का वरिष्ठ अधिकारी भली-भाँति परीक्षण कर लें। उन्होंने आमजन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैम्प में राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी तथा नई न्याय संहिताओं पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर शाह राज्य के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, मेयर नगर निगम हरिद्वार किरन जैसल, मेयर नगर निगम रूड़की अनीता देवी, नगर पालिका ऋषिकेश के अध्यक्ष शंभू पासवान, पूर्व विधायक स्वामी यतीश कुंभ मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उपजिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार तथा एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नमाजियों ने अल्लाह की बारगाह में खास दुआएं की

देहरादून(संवाददाता)। मुकद्दस माह-ए-रमजान का तीसरा जुमा देहरादून में अकीदत और एहतराम के साथ अदा किया गया। शहर की मस्जिदों में नमाजियों ने अल्लाह की बारगाह में खास दुआएं की गईं। शहर काजी ने बताया कि रमजान के पहले जुमे पर गेहूं के हिसाब से 50 रुपये प्रति व्यक्ति सदका-ए-फितर का ऐलान किया जा चुका है। अब स्थानीय बाजार में अनाज और दूसरी चीजों की मौजूदा कीमतों की मुफ्ती सलीम अहमद कासमी की तहकीक के बाद बाकी दरें भी तय कर दी गई हैं। इसके मुताबिक आटा के हिसाब से 62 रुपये, जौं के हिसाब से 140 रुपये, खजूर और छुहारे के हिसाब से 1050 रुपये, पनीर के हिसाब से 1270 रुपये और किशमिश के हिसाब से 1650 रुपये प्रति व्यक्ति सदका-ए-फितर तय किया गया है।

सारा (SARA) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न

देहरादून(संवाददाता)। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी (सारा) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्व बैंक पोषित जलागम विकास, जल निकायों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, पारंपरिक नौलों-धारों के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।सॉन्ग और कमल नदी परियोजनाओं की समीक्षा: बैठक में देहरादून की सॉन्ग नदी तथा उत्तरकाशी की कमल नदी से संबंधित दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त 23 अप्रैल 2025 को आयोजित सारा की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा भी की गई।सॉन्ग नदी परियोजना के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना : मुख्य सचिव ने सॉन्ग नदी से जुड़े क्षेत्रों का विस्तृत चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए, जहाँ सुधार एवं हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों के अनुसार आवश्यक कार्यों का निर्धारण कर संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उनकी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कराई जाए।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परियोजना के क्रियान्वयन के बाद उसके प्रभाव (इंपैक्ट) का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया जाए। इसके लिए आईआईटी रुड़की जैसे तकनीकी संस्थानों के सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया।

सीडीओ के निरीक्षण में 34 कर्मचारी गैरहाजिर, वेतन रोकने के निर्देश

बागेश्वर (संवाददाता)। होली पर्व समाप्त होने के बाद भी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने विभिन्न विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 30 कार्यालयों में कुल 34 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि सिंचाई विभाग के ईई और जिला युवा कल्याण अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। सीडीओ ने सबसे पहले अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। इसके बाद जीआईएस सेल, बहुद्देशीय वित्त, कृषि, उद्यान, कृषि एवं भूमि संरक्षण, पंचस्थानी, बाल विकास, पशुपालन, पीआरडी, डेयरी, रीप परियोजना, उरेडा, मत्स्य, जिला पंचायत राज, ग्रामीण विकास विभाग, ब्लॉक कार्यालय बागेश्वर, लघु सिंचाई, सिंचाई उपखंड, लोनिवि, जल संस्थान, पीएमजीएसवाई, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा समग्र शिक्षा कार्यालयों का निरीक्षण किया।निरीक्षण में सबसे अधिक आठ कर्मचारी लोक निर्माण विभाग से अनुपस्थित मिले। इसके अलावा लघु सिंचाई में छह, जीआईएस सेल में एक, बहुद्देशीय वित्त में दो, कृषि में दो, बाल विकास में एक, मत्स्य में दो, सिंचाई उपखंड में दो, सिंचाई खंड में दो, जल संस्थान में एक, पीएमजीएसवाई में तीन, मुख्य शिक्षा कार्यालय में एक, जिला शिक्षा कार्यालय में एक तथा समग्र शिक्षा में दो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की आबरू लूटने से बच गई

हल्द्वानी (संवाददाता)। पड़ोसियों की जागरूकता से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की आबरू लूटने से बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।जानकारी के अनुसार नवाबी रोड वार्ड 11 मे 28 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त युवती रहती है। युवती के परिवार में कोई न होने के कारण पड़ोसी ही उसकी देखभाल करते हैं। गुरुवार देर रात लगभग 1:30 बजे एक युवक खिड़की की दीवार तोड़कर युवती के घर में घुस गया। दीवार टूटने की आवाज पर जब पड़ोसी पहुंचे तो उन्होंने कमरे में घुसे युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है।क्षेत्रवासियों के अनुसार आरोपी युवक का नाम करन है जो ऑटो चालक है। शुक्रवार को क्षेत्रीय पार्षद रवि जोशी क्षेत्र की महिलाओं के साथ कोतवाली पहुंचे। महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ तहरीर सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार...

जन औषधि दिवस पर पैदल यात्रा निकालकर किया जागरूकता

देहरादून(संवाददाता)। जन औषधि दिवस के अवसर पर टैगोर विला स्थित चिल्ड्रंस अकादमी के पास से पैदल यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में पैदल जन जागरूकता अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम जनता को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने पर आभार जताया। मुकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी की जरूरत को समझा हैं और उन्हें महंगी दवा से निजात दिलाने के लिए जन औषधि केंद्र का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड नोडल अधिकारी शिवम राघव ने कहा कि जन जन ने ठाना है जन औषधि को अपना कर स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। पैदल यात्रा में हरीश नारंग, डॉ आनंद यादव व आदि लोग मौजूद रहे।

भीषण गर्मी की चुनौतियों पर हुआ संवाद

देहरादून(संवाददाता)। शहर में बढ़ती तपिश से निपटने के लिए शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित होटल में एक विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। 'वर्ड्स, रिदम्स, इमेजेस' और 'आर्यन ग्रुप' की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय 'एक्सट्रीम हीट: स्टोरीटेलिंग के माध्यम से सामुदायिक कार्रवाई' रहा। मुख्य अतिथि और जलवायु कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने इसे शहर की पहली केंद्रित पहल बताया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की डॉ पूजा राणा ने भी इस कार्य को सराहा। अजय गोविंद और फैजी खान के नेतृत्व में काठबंगला और नागल बस्ती के बच्चों और महिलाओं ने डिजिटल कहानियों के जरिए गर्मी के अपने अनुभव और समाधान साझा किए। वक्ताओं ने जोर दिया कि बढ़ती गर्मी से लड़ने के लिए सामुदायिक एकजुटता और स्थानीय छोटे बदलाव अनिवार्य हैं।

हिन्दी दैनिक जोखिम

टिहरी झील बनी रोमांच और पर्यटन का नया केंद्रः सीएम

- मुख्यमंत्री धामी ने किया हिमालयन 0.2 फेस्टिवल का शुभारंभ

देहरादून(संवाददाता)। पर्यटन, साहसिक खेल के साथ ही पर्यावरण और संस्कृति के स्पष्ट संदेश के बीच शहिमालयन 0.2 द टिहरी लेक फेस्टिवलश का भव्य शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन करते हुए विश्वास प्रकट किया कि सुंदर टिहरी झील आने वाले समय में देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में साहसिक खेलों और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगी। इस मौके पर उन्होंने घोषणा कि कोटी कालोनी-नई टिहरी रोपवे का निर्माण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में देश-विदेश से आए खिलाड़ियों के साथ ही अन्य मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा आध्यात्मिकता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम रही है। हमारी नदियां, हमारे पर्वत, हमारी झीलें और हमारी परंपराएं पूरे विश्व को आकर्षित करती रही हैं। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित ये महोत्सव पर्यटन, खेल और स्थानीय संस्कृति तीनों को एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण होने के साथ- साथ साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में तेजी से उभर रही है। यहां आयोजित होने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने का काम भी कर रही हैं।मुख्यमंत्री ने टिहरी को लेकर अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जेट-स्की, पैरा-सेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य साहसिक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ताकि हमारे युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि टिहरी झील के आसपास विकसित हो रहा यह खेल और पर्यटन तंत्र स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर पैदा कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि टिहरी झील केवल एक पर्यटन स्थल ही न रहे, बल्कि खेल, संस्कृति और प्रकृति के संगम का वैश्विक केंद्र भी बने। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से भावनात्मक लगाव जगजाहिर है और उन्होंने स्वयं यहां आकर हमें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन और साहसिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का खास तौर पर जिक्र किया। इस क्रम में उन्होंने आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई-एल्टीट्यूड मैराथन, माणा में एमटीबी चौलेंज, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे बडेष् स्तर के आयोजनों की चर्चा की।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा केवल अवसरों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने सामर्थ्य और परिश्रम से नए अवसरों का सृजन भी करें। उन्होंने कहा कि आज टिहरी में 400 से अधिक युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह जानकारी खुशी देने वाली है। पूर्ण विश्वास है कि ये युवा भविष्य में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करने में अवश्य सफल रहेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने टिहरी क्षेत्र में विकास कार्यों की तस्वीर को सामने रखा। उन्होंने बताया कि टिहरी क्षेत्र के के समग्र विकास हेतु लगभग 1300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। इसमें टिहरी झील का विकास, रिंग रोड का निर्माण, तिमाड़ गांव को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। इसके अलावा यहां भिलंगना विकासखंड की सुनारगांव ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। विशिष्ट पहाड़ी शैली में एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में जिले के सभी ब्लाक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 10 कॉम्पेक्टर केंद्रों और 4267 कूड़ा संग्रहण केंद्रों की स्थापना का भी जिक्र किया।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक किशोर उपाध्याय, विक्रम सिंह नेगी, विनोद कंडारी, शक्तिलाल शाह, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण, जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल, नगर पालिका परिषद नई टिहरी के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत व चंबा की अध्यक्ष सोबनी धनोला, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने देवडोलियों से आशीर्वाद भी लिया ।कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का शिलान्यासः कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोटी-डोबरा पर्यटन मार्ग का रिमोट दबाकर वर्चुअल शिलान्यास किया। यह मार्ग एशियन डेवलपमेंट बैंक के स्तर पर वित्त पोषित है,जिसकी कुल लागत 318 करोड़ है। इस मार्ग की लंबाई करीब 15 किलोमीटर है।

नौ मार्च तक होंगी विभिन्न गतिविधियांः टिहरी लेक फेस्टिवल में नौ मार्च तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साहसिक खेल व पर्यटन गतिविधियों के अलावा लोक संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

जुआ खेलने और जुआघर चलाने पर अब सख्त सजा का प्रावधान

देहरादून (संवाददाता)। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक में जुआ खेलने और खिलाने की गतिविधियों में संलिप्त दोषियों के लिए न्यूनतम तीन माह से लेकर अधिकतम पांच साल तक जेल और पांच हजार से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक-2026 को सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन कर नेपाली अकादमी को शामिल किया गया।वर्तमान में राज्य में केंद्र सरकार का वर्ष 1867 का गैंबलिंग एक्ट लागू है। इस एक्ट में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआ घर चलाने पर मामूली जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक द्यूत रोकथाम कानून लागू होने के बाद राज्य में जुआ खेलने और सट्टेबाजी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, सड़क और गली में सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने पर तीन माह का साधारण कारावास या पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। घर में बैठाकर जुआ खिलाने पर दो साल की जेल या दस हजार रुपये जुर्माना, जुआघर चलाने पर पांच साल की जेल या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों ही सजा एक साथ लागू होगी। सिंडीकेट की तरह सट्टेबाजी आदि जुए की गतिविधि चलाने पर न्यूनतम तीन से पांच साल तक जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।नेपाली अकादमी को मिला स्थानउत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 में वर्तमान हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी भाषा शामिल थी। अब कैबिनेट ने उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें उत्तराखंड नेपाली अकादमी को भी शामिल किया गया। इससे नेपाली साहित्य को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है।

नैनीताल की झीलों का होगा कायाकल्प, भीमताल-नौकुचियाताल और कमलताल विकास योजनाओं को मिली रफ्तार

- सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने ली झीलों के पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण परियोजना से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक

देहरादून(संवाददाता)। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन जनपद नैनीताल की झीलों को और अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में जनपद नैनीताल की आवास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नैनीताल के जिलाधिकारी डॉ. ललित मोहन रयाल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उप सचिव आवास रजनीश जैन, अनुसचिव वित्त गौरीशंकर जोशी और राज्य सरकार के विशेष सलाहकार जी.पी. पंत भी मौजूद रहे।

भीमताल झील के सौन्दर्यीकरण पर विशेष जोरः समीक्षा बैठक में भीमताल झील के पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2567.49 लाख रुपये निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य भीमताल झील क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से अधिक आकर्षक, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके और क्षेत्र का समग्र विकास हो।पाथ-वे, पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी विकसित : परियोजना के तहत झील के चारों ओर आकर्षक और सुरक्षित पाथ-वे का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटक झील के चारों ओर आसानी से घूम सकेंगे। इसके अलावा सुभाष पार्क और दीनदयाल पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। योजना में लगभग 40 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग, लैंडस्केपिंग, आधुनिक उपकरणों की स्थापना, ओपन सिटिंग एरिया का निर्माण तथा बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पूरे क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युतीकरण का कार्य भी किया जाएगा। नौकुचियाताल और कमलताल के विकास की भी योजना : बैठक में नौकुचियाताल झील और कमलताल झील के पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2097.02 लाख रुपये आंकी गई है।

हिन्दी दैनिक जोखिम

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई यूसीआरआरएफपी की बैठक

- हाई पावर कमेटी ने 187.11 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को दी मंजूरी

- अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा

देहरादून(संवाददाता)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना की हाई पावर कमेटी (भ्च्छ) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए 187.11 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया।2025ख्26 की संशोधित कार्ययोजना को भी स्वीकृति: यूसीआरआरएफपी की चतुर्थ हाई पावर कमेटी की बैठक में समिति ने वित्तीय वर्ष 2025ख्26 की 62.19 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित वार्षिक कार्ययोजना को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए तैयार परियोजना संचालन दिग्दर्शिका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल तथा विभिन्न प्रपत्रों और दिशानिर्देश पुस्तिकाओं का अनुमोदन किया गया।ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाए परियोजना का लाभ: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि ग्रामीणों को परियोजना का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए परियोजना के माध्यम से बारानी कृषि को अधिक सक्षम और टिकाऊ बनाया जाना आवश्यक है। बैठक में सचिव/मुख्य परियोजना निदेशक दिलीप जावलकर, सचिव सी रविशंकर, परियोजना निदेशक हिमांशु खुराना, अपर सचिव अपूर्वा पांडेय, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा कहकशां नसीम, संयुक्त निदेशक डा. ए.के. डिमरी, मुख्य वित्त अधिकारी दीपक भट्ट, उप निदेशक डा. एस.के. उपाध्याय, डा. डी.एस. रावत, डा. सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

22 वर्षों से लापता युवक को मृत दिखा हड़पी करोड़ों की जमीन

देहरादून(संवाददाता)। दून में जमीन हड़पने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 22 साल से लापता एक युवक को कागजों में मृत दर्शाकर उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और फिर करोड़ों की जमीन पहले मां के नाम दर्ज करवाई और बाद में उसे बेच डाला। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने इस विवादित जमीन पर बैंक से लोन भी ले लिया। मूल रूप से नालासोपारा, महाराष्ट्र निवासी बुजुर्ग महिला प्रतिमा लाखीराम कंसवाल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अर्जुन सिंह भंडारी ने आईजी गढ़वाल को दी शिकायत में बताया कि अजबपुर खुर्द में उनके बेटों विनोद और राकेश के नाम 406 वर्गमीटर जमीन है। छोटा बेटा राकेश साल 2004 से मुंबई से लापता है। जमीन खरीदने के बहाने प्रदीप सकलानी नाम के व्यक्ति ने परिवार का भरोसा जीता और लापता बेटे को कोर्ट के जरिए मृत घोषित कराकर जमीन मां के नाम कराने का झांसा दिया। आरोपी ने जमीन के कागजात और आधार कार्ड हासिल करने के बाद बड़े पैमाने पर जालसाजी की।

संक्षिप्त समाचार...

महिला को टक्कर मार कार चालक ने इंस्पेक्टर बता रौब दिखाया

देहरादून(संवाददता)। राजपुर रोड पर वीएलसीसी के पास गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार वकील की पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि शराब के नशे में कार चालक ने मौके पर हंगामा किया और खुद को विजिलेंस का इंस्पेक्टर बताते हुए महिला और उसके वकील पति को धमकियां दीं। मामले में डालनवाला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वेस्ट पटेलनगर निवासी करण सहगल ने कहा कि पांच मार्च की शाम करीब 6:30 बजे उनकी भाभी अर्चना उपाध्याय सहगल राजपुर रोड से गुजर रही थीं। तभी पीछे से आ रही कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिर गईं। वहां मौजूद लोगों ने चालक को पकड़ लिया। जिसने अपना नाम बिजेंद्र भटोला बताया। आरोप है कि चालक नशे में था और उसने घायल महिला को धमकी दी कि वह विजिलेंस में है और पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। सूचना पर जब पीड़िता के पति अधिवक्ता वीरेंद्र सहगल मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें भी कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। हादसे में अर्चना के सीधे पैर का मांस फट गया है। हाथी बड़कला चौकी इंचार्ज सतबीर भंडारी ने बताया कि तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विजिलेंस नहीं आईटीबीपी का इंस्पेक्टर है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

भारतीय परंपराओं से हमारी पीढ़ियों का जुड़े रहना जरूरी

देहरादून(संवाददता)। दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्यूनिकेशन स्टडीज में शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के कल्चर एंड मीडिया स्टडीज विभाग के डीन प्रो अमिताभ श्रीवास्तव ने भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संचार माध्यमों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। उन्होंने समय के साथ संचार के माध्यमों में आए बदलावों और इससे समाज के बदले परिदृश्य की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराएं हमारी जड़े हैं। जिनसे हमारी पीढ़ियों का जुड़े रहना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहानीकार जोजेफ कैंपबेल का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय दर्शन पर उनके विचार आज भी विश्व सिनेमा की कहानियों का हिस्सा बना हुआ है। विभागाध्यक्ष डॉ राजेश कुमार ने नाट्य शास्त्र में विदित सहृदयता के मूल मंत्र पर प्रकाश डाला।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पोस्ट बजट बेविनार कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग

देहरादून(संवाददाता)। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। यह वेबिनार अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसे गिरीदार फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में किसानों की आय बढ़ाने और औद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए सरल एवं प्रभावी नीतियां लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अखरोट, बादाम और पाइन नट्स को बढ़ावा देने की घोषणा किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के साथ-साथ किसानों की भी उतनी ही चिंता करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखण्ड चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में औद्यानिकी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें सेब की अति सघन बागवानी, उत्तराखण्ड कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग, सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना, मधुमक्खी पालन नीति और अत्याधुनिक सेब नर्सरी विकास योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में लगभग 5642 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अखरोट की खेती की जा रही है, जिससे करीब 8995 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अखरोट और बादाम की खेती के लिए बेहद अनुकूल हैं तथा इन फसलों को जंगली जानवरों से भी कम नुकसान होता है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना रहती है।कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अखरोट की खेती को क्लस्टर आधारित मॉडल पर बढ़ावा दिया जाए और बादाम सहित अन्य गिरीदार फलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत प्रजातियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की पौधशालाओं में वर्तमान में अखरोट के 42,699 और बादाम के 630 पौधे उपलब्ध हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि गुणवत्तायुक्त फल पौध तैयार करने के लिए राजकीय उद्यानों और नर्सरियों को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराए जा सकें।इस दौरान कृषि मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के उद्यानों और पौधशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 415 मालियों की भर्ती प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को शीघ्र दूर कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।इस अवसर पर निदेशक उद्यान सुंदर लाल सेमवाल, बागवानी मिशन निदेशक महेंद्र पाल, रतन कुमार सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक संजीव पंत द्वारा जेल रोड, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं चिराग पब्लिकेशन जेल रोड, हल्द्वानी नैनीताल से मुद्रित। सम्पादक - राजेश पंत
फोन नं0- 05946-254443 प्रसार प्रबंधकः वसीम अहमद , आर एन आई नं.: UTTHIN/2010/36647 email: jokhimhaldwani2013@gmail.com
ताज़ातरीन खबरों व सही जानकारी के साथ समाचार को विस्तार से पढ़नें के लिए लागआन करें हमारा newsportal:. jokhimnews.com